भारतीय पटसन निगम

*265. **श्रीममी सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार ने पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए वर्ष 1971 मे भारतीय पटसन निगम का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संगठन में कोई निवेश भी किया हैं;

(ग) यदि हां, तो संगठन मे बाद में विभिन्न चरणों मे विभिन्न स्रोतों से निवेश की गई पूंजी सहित प्रारंभिक निवेश कितना हैं;

(घ) क्या यह भी सच हैं कि इस समय निगम घाटे में चल रहा हैं; और

(ड.) यदि हां, तो मार्च, 1995 के अंत तक निगम को कुल कितना घाटा हुआ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जूट कारपोरेशन आफ इंडिया (जेसीआई) की स्थापना 1971 में अन्य बातों के साथ-साथ पटसन और मेस्टा को खरीदने तथा बेचने के लिए की गई थी। जेसीआई पटसन उपजकर्त्ताओं के हित में मूल्य समर्थन प्रचालन चला रहा हैं।

(ख) जेसीआई भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन हैं तथा इसकी प्राधिकृत तथा अभिदत्त पूंजी 5 करोड़ रू. हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा जेसीआई की शेयर पूंजी के लिए किए गए निवेश के वर्ष –वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	निवेश (करोड़ रू.)
1971-72	0.75
1972-73	0.25
1974-75	1.00
1975-76	1.00
1982-83	2.00
कुल:	5.00

(घ) और (ड.) 31.3.1995 तक जेसीआई को कुल घाटे 318.05 करोड़ रू. (अनंतिम) के हुए।

Drug addicts in Delhi

*266. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of drug addicts in Delhi; and

(b) the steps taken by Government to check the smuggling of drugs and to educate the people of the effect thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHARA MURTHY): (a) According to the reports received from De-addiction-cum-Rchabilitation Centres and Drug Awareness, Counselling and Assistance Centres being run by Non-Governmental Organisations with financial assistance from the Ministry of Welfare under the Scheme of 'Prohibition and Drug Abuse Prevention', the number of Drug Addicts in Delhi during 1994-95 is 37207.

(b) Instructions have been issued to afl the enforcement agencies to maintain the utmost vigi! and step up enforcement efforts under the stringent provisions contained in NDPS Act. Training is being imparted to officers to improve their effectiveness. A part of Indo-Pak border has been fenced. BSF and Coast Guards, who are deployed on land and coastal borders have been vested with the powers under the Customs Act to interdict narcotic drugs on the border in addition to the Central and State Government enforcement agencies empowered under the NDPS Act.

Reward scheme for informers and enforcement officers is being implemented zealously. Coordination meetings are being held periodically at the Central and State level to review the working of enforcement agencies and to exchange intelligence on drugs trafficking.

The Central Government has launched a massive Awareness Generation Programme to educate people about the ill-effects of drug abuse.